



जगत प्रवाह



वर्ष : 15 अंक : 25

प्रति सोमवार, 28 अक्टूबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

कमलनाथ की सक्रियता से मध्यप्रदेश कांग्रेस में आई स्फूर्ति

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

अपने पांच दशकों का राजनीतिक अनुभव और दक्षता के कारण कमलनाथ अभी भी कांग्रेस पार्टी की ताकत बने हुए हैं। छिन्दवाड़ा को अपना परिवार मानने वाले कमलनाथ ने यहां राजनीति नहीं की अपितु एक पारिवारिक संबंध के जैसे हर रिश्ता निभाया। चाहे खेती, रोजगार, विकास, दिल्ली में छिन्दवाड़ावासियों का उच्च श्रेणी का इलाज हर प्रकार की सेवा इस बेटे ने अपने क्षेत्र के लिए की है। आज लोकसभा चुनाव के 05 महीने बाद ही छिन्दवाड़ा को अपने बेटे की याद आने लगी है। कमलनाथ हमेशा कहते हैं कि छिन्दवाड़ा से उनका राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता है और उसी फ्रंट के नाते वो यह रिश्ता निभा रहे हैं। (शेष पेज 8 पर)



क्या हनुमान भक्त कमलनाथ कांग्रेस के लिए बनेंगे संकटमोचक? क्या कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के बीच सेतु का काम करेंगे कमलनाथ? देश के उद्योगपति मानते हैं कमलनाथ को अपना मेंटर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पार्टी आलाकमान राहुल गांधी की मुलाकात के क्या हैं मायने?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेक पहल से राज्य की लाखों छात्राओं के सपनों को मिले पंख

-विजया पाठक

किस्ती भी सध्य और सशक्त समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब वहां के युवा-युवती शिक्षित हों, उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें और उनके हाथ में रोजगार हो। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। खास बात यह है कि साय सरकार ने न सिर्फ कमजोर और गरीब वर्ग के लिये जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं बल्कि उन्होंने राज्य की छात्राओं और युवतियों को आत्मनिर्भर, शिक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साय सरकार द्वारा उठाये गये इस महत्वपूर्ण कदम का लाभ प्रदेश की लाखों युवतियों को मिल रहा है और अब युवतियां पढ़लिखकर अपने सपनों को पंख लगाने का काम कर रही हैं।



युवाओं के सपने होंगे साकार

छात्रा हित में लिया बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खुद सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। सीएम ने कहा- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में न हो कोई दिक्कत और उनका भविष्य हो उज्ज्वल, यही हमारी सरकार का लक्ष्य है। 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना' के तहत नक्सल प्रभावित 17 जिलों के विद्यार्थियों को 04 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण और शेष जिलों के विद्यार्थियों को 01 प्रतिशत ब्याज पर ऋण हमारी सरकार देगी।

कितना मिलेगा लोग

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत छात्रों का 04 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। जानकारी के अनुसार, यह लाभ 35 व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को कवर करेगा। सरकार की इस योजना का मकसद है कि नक्सल प्रभावित जिलों में युवा नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ जाएं। नक्सल प्रभावित जिलों के लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना फोकस करें। (शेष पेज 8 पर)



2 खिलाड़ियों ने की कलेक्टर से कबड्डी मैट की मांग



5 शिवसेना को नई दशा और दिशा दी उद्धव ठाकरे ने



8 भारत के शीर्ष 50 पत्रकारों में से एक हैं अशुभन



खिलाड़ियों ने की कलेक्टर से कबड्डी मैट की मांग

-प्रमोद वरसेले

उमगत प्रवाह, टिहरीवाली। न्यू एसबी एस कबड्डी क्लब के सचिव अंकित जोशी के साथ समस्त कबड्डी खिलाड़ी जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचे। जहां उन्होंने कलेक्टर को खेल सामग्री की मांग के लिए आवेदन दिया। पिछले दो वर्षों से खेल एवं युवक कल्याण विभाग के द्वारा समर कैंप में कोई भी खेल सामग्री या मानदेह नहीं दिया

जा रहा। जबकि विभाग के द्वारा कागज पर संपूर्ण करवाई खिलाड़ियों एवं कोच के द्वारा कराई जा चुकी है जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में क्लब के लगभग 100 खिलाड़ी प्रतिदिन कन्या शाला में मिट्टी के मैदान पर अभ्यास करते हैं जबकि अब कबड्डी मैट पर खेली जाती है। आगामी 21 नवंबर से जबलपुर में कबड्डी

प्रतियोगिता का आयोजन होना है जिसके लिए खिलाड़ी के पास मैट उपलब्ध नहीं है इसके लिए कलेक्टर को सभी खिलाड़ियों ने जनसुनवाई में जाकर आवेदन दिया। कलेक्टर ने शीघ्र ही खिलाड़ियों को खेल सामग्री देने का आश्वासन दिया। आवेदन देते समय कोच अंकित जोशी, दीपक पटवारे, राजकुमार चंदेल, दीपक गौर नीतिष्ठा चोराशी मौजूद रहे। (जगत फीचर्स)

1 नवंबर से शुरु होगी अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना



-संवाददाता

उमगत प्रवाह, रायपुर। छत्तीसगढ़ के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार तीन नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। तीन नई योजनाओं का अनुमोदन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सत्रिमांण कर्मकार कल्याण मंडल की तीसरी बैठक में लिया गया। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 01 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी। इसी तरह निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत होगी। साथ ही प्रदेश के 26.68 लाख निर्माणी श्रमिकों और उनके बच्चों को कौशल उन्नयन के लिए निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना भी शुरू की जाएगी। बैठक में श्रम विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल वर्मा, बीओसी की सचिव सविता मिश्रा, मुख्य निरीक्षक सह श्रमावृत्त एसएस पैकर समेत दूसरे अधिकारी मौजूद रहे।

बड़े स्तरों में पढ़ेंगे श्रमिकों के बच्चे: संचालक मंडल की बैठक में श्रम मंत्री सह अध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की श्रमिक सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर ब्यात की। मंत्री ने शाहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत सभी जिलों में योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए।

बिना पंजीकृत श्रमिकों के मृत्यु पर भी मंडल देगा 01 लाख: मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत बृथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर 05 लाख, स्थाई दिव्यांगत में ढाई लाख, सामान्य मृत्यु पर उनके वैध उत्तराधिकारी को एक लाख की राशि दी जाती है। लेकिन अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मृत्यु उपरांत राशि देना का प्रावधान नहीं है। (जगत फीचर्स)

राष्ट्रपति के हाथों मेधावी छात्रों को मिला स्वर्ण पदक, द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आईआईटीयन्स ने वैश्विक स्तर पर बनाई विशेष पहचान

-संवाददाता

उमगत प्रवाह, रायपुर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संस्थान की तृतीय एवं चतुर्थ दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर संस्थान के विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अपने हाथों से स्वर्ण पदक दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के लिए 26 अक्टूबर का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों उनके अभिभावकों, प्राध्यापकों, सचिवों को भी बधाई दी।

उन्होंने कहा कि आज का दिन आपके लिए खुद को यह याद दिलाने का दिन है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक और सक्षम व्यक्ति के रूप में बाहर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई द्वारा आदिवासी समाज की प्रगति के लिए तकनीकी क्षेत्र में किए गए विशेष प्रयास सराहनीय हैं। आईआईटी भिलाई ने ऐप्रोपेट, हेल्थटेक और थिंकटैक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। आईआईटी भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एएस रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिसके माध्यम से गांव के लोगों को घर बैठे चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। (जगत फीचर्स)



जनसुनवाई में 170 आवेदन प्राप्त हुए, कलेक्टर द्वारा मौके पर 98 आवेदनों का निराकरण

-कैलाशचंद्र जैन

उमगत प्रवाह, विट्टिशा। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के द्वारा आहुत साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में अधिकांश आवेदनों का निराकरण हो रहा है। कलेक्टर स्वयं तमाम आवेदनों के निराकरणों की विभागावार पृथक-पृथक समीक्षा कर रहे हैं। जिसमें विगत जनसुनवाई के लंबित आवेदनों पर निराकरण की अद्यतन स्थिति से अधिकारी अवगत करा रहे हैं। कलेक्टर सिंह के द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में खण्ड स्तरीय अधिकारी भी सीधे वीडियो

कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहते हैं और आवेदकों के आवेदनों से अवगत होकर निराकरण की पहल कर रहे हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचने के पहले कक्ष के बाहर ही अपनी परियाद लेकर पहुंचे सिरोंज तहसील के ग्राम पथरिया के ज्ञान सिंह आदिवासी की समस्या को गंभीरता से सुना। इस दौरान आवेदक ने जाति प्रमाण पत्र और आवास संबंधित समस्या से अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर श्री सिंह ने मौके पर ही संबंधित अधिकारी से संवाद कर आवेदक की समस्या का जल्द से

जल्द निराकरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में 170 आवेदकों ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है। कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा मौके पर 98 आवेदनों का निराकरण किया गया है। कलेक्ट्रेट के भूतल कक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार समेत विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। (जगत फीचर्स)



4 साल की पूरी प्रतिनियुक्ति के बाद शिक्षकों को स्कूल नहीं लौट रहे डीपीसी

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह, नरमिहपुर। राज्य

शिक्षा केंद्र भोपाल और विभागीय गाइडलाइन का पालन जिला शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान नरमिहपुर के मुखिया डॉ. आरपी चतुर्वेदी डीपीसी और वर्तमान प्रभारी एपीसी गण द्वारा नहीं किया जा रहा है। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के प्रतिनियुक्ति नियमों में स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति तिथि से 4 साल की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति से खपस किया जाना है और नई प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। यह शर्त प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले विकासखंड एकेडमिक समन्वयक और जनशिक्षकों के नियुक्ति आदेश में भी स्पष्ट रूप से लिखी गई है परंतु जिला शिक्षा केंद्र नरमिहपुर स्वयं के बनाए गए नियुक्ति आदेश में लिखी शर्त का पालन नहीं कर रहा है।

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी नरमिहपुर कार्यालय की हीलाहवाली भी संदेह के घेरे में बनी हुई है। मामला 4 साल पुरानी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी कर चुके अमले को हटाकर संभावित रिक्तियों के विरुद्ध नई प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को है।

चार साल बाद प्रतिनियुक्ति बढ़ाने नहीं हैं कोई निर्देश

नरमिहपुर जिले में विगत 30 दिसंबर 2019 को बीपीसी और सीपीसी के पदों हेतु काउंसिलिंग की गई थी इसके उपरान्त आज 4 वर्ष से अधिक समय व्यतीत जाने के बाद

भी नई प्रतिनियुक्ति के लिए और पुराने अमले को हटाने के किसी प्रकार के कोई दिशा निर्देश और आदेश जारी नहीं किए गए। इसके पूर्व तत्कालीन डीपीसी रहे उसके कोष्टी और वर्तमान समय में डीपीसी आरपी चतुर्वेदी द्वारा प्रतिनियुक्ति के 2 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद नियुक्ति अमले में आयुसीमा पार कर चुके एवं गलत विषय से चयनित अपात्र प्रतिनियुक्ति धारी और अन्य पात्रता और कार्य व्यवहार का ना तो परीक्षण ही किया गया और ना ही इसके लिए समीक्षा बैठक रखी गई जोकि एक बड़ी विभागीय लापरवाही है। इसके लिए पूर्व में अनेक शिक्षासत अमले की कार्य व्यवहार और पात्रता की समीक्षा की मांग की गई थी जिन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन सबको एक साथ तत्काल हटाने की मांग हो रही है।

प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी अब वेतन मद भुगतान में बंदरबांट

प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने वाले अमले को दिया जाने वाला वेतन और भले वित्तीय गफलत के अंतर्गत आता है क्योंकि 4 साल के बाद प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया बढ़ाने राज्य शिक्षा केंद्र ने कोई नीति नियम निर्देश नहीं बताया गया है और बिना स्पष्ट मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के बिना अनुमति के इस तरह अमले को वेतन भत्ते देना वित्तीय अनुदान की बंदर बांट करने के समान है जो कि नरमिहपुर डीपीसी कार्यालय द्वारा आपत्तिजनक ढंग से घोटाले की तर्ज पर अंजाम दिया जा रहा है।

(जगत फीचर्स)

फिल्म एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के करकमलों से डॉ. डीके सोनी को मिला आई कोन ऑफ इंडिया का बेस्ट एडवोकेट एंड आरटीआई एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड

-संवाददाता

जगत प्रवाह, रायपुर। मुंबई के होटल जिंजर में टाइम्स एप्लाइड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित समारोह में अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. डीके सोनी को फिल्म एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के करकमलों से सम्मान

दिया गया। इसके पूर्व 32 एवार्ड मिल चुके हैं यह इनका 33वां अवार्ड है। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी के द्वारा हमेशा न्याय में देरी, भ्रष्टाचार एवं विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा हेतु अनेक उत्कृष्ट कार्य किए जाते रहे हैं। डॉ. सोनी आमजन के लिए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम और शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु अपनी संस्था सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के माध्यम से हमेशा जमीनी स्तर पर एवं आरटीआई के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर

माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सफल और निर्णायक कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। डॉ. डीके. सोनी द्वारा सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को लेकर अनेकों मामले उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुलासा कर दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही कराकर कई भ्रष्ट अधिकारियों, टेकेदारों के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध कराया गया है। टाइम्स एप्लाइड प्राइवेट लिमिटेड के चयन समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक एवं कानूनी स्तर पर तथा फिल्मी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का भी चयन किया गया जिसमें सरगुजा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में आरटीआई एवं अन्य

कानूनी के माध्यम से लगातार सामाजिक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अंबिकापुर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. डीके सोनी को देश के कोने कोने से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई फिल्मी तथा टीवी एक्टरों के समक्ष होटल जिंजर मुंबई में फिल्म एक्ट्रेस और

सुप्रसिद्ध हिरोइन करिश्मा कपूर के करकमलों से आई कोन ऑफ इंडिया का बेस्ट एडवोकेट एंड आरटीआई एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। मुंबई के उक्त कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ फिल्मी और टीवी के अनेक एक्टर जिसमें अहसान कुरैशी, अभिषेक कपूर के अलावा कई टीवी एक्टर उपस्थित थे को भी सम्मानित किया

गया। उक्त अवार्ड कार्यक्रम का संचालन पूर्व मिस इंडिया सिमरन आहूजा ने की तथा कार्यक्रम में टाइम्स एप्लाइड के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर नितिन गोहिल भी उपस्थित थे। अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी को उक्त अवार्ड मिलने से उनके शुभचिंतकों सहित अधिवक्ताओं और सोशल जस्टिस प्राप्त करने वालों में हर्ष व्याप्त है। इस मौके डॉ. डीके सोनी ने यह कहा है कि यह अवार्ड उनके द्वारा किए जा रहे जनहित और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा देता है और भविष्य में आगे अधिक ऊर्जा से तेज गति से सामाजिक और जनहित के कार्य को करने प्राथमिकता दिया जायेगा।

(जगत फीचर्स)

अपने बीच कलेक्टर को पाकर खुशी से झूम उठे दिव्यांग बच्चे, कलेक्टर सुश्री मीना ने सामग्री खरीद कर बच्चों का किया उत्साहवर्धन

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह,

जर्जापुरम। दिव्यांग संस्था में दिव्यांग बच्चों द्वारा दिव्यांगी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार हस्तकला उत्पादन का निर्माण एवं लक्ष्मी प्रतिमा बनाए गए हैं जिसे देखने नरमिहपुरम कलेक्टर सोनिया मीना एवं डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौर ने संस्था में बच्चों के द्वारा बनाए गए उत्पादकों को देखा और दिव्यांगजनों की बनाई सामग्री खरीद कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया एवं उनके शिक्षण प्रशिक्षण कौशल विकास की जानकारी सुश्री अफरोज खान से ली। कलेक्टर को अपने बीच पाकर दिव्यांग बच्चे खुशी से झूम उठे। कलेक्टर ने कहा कि



मुझे इन बच्चों के बीच आकर, उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा एवं उन्होंने बच्चों के व्यावहारिक कौशल की सराहना की। संस्था द्वारा बच्चों को दिया जा रहे प्रशिक्षण एवं रचनात्मक कार्य की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर संस्था

अध्यक्ष योगेश शर्मा द्वारा बताया गया कि संस्था बच्चों द्वारा बनाए गए उत्पादों का स्टाल विवेकानंद घाट पर 29 एवं 30 अक्टूबर को प्रदर्शन हेतु लगाया जाएगा। इस अवसर पर संस्था में सभी सहयोगी सदस्य उपस्थित थे। (जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ और हत्या की घटनाएं भयभीत करने वाली हैं

विगत महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हत्या पर राष्ट्रपति की पीड़ा ध्यान देने योग्य है। उन्होंने बहुत दृढ़ भरे शब्दों में कहा कि मैं निराश और भयभीत हूँ। कहना न होगा कि नौ अगस्त को कोलकाता में घटित इस दर्दनाक घटना के बाद उनका यह पहला बयान है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि कोई भी सभ्य समाज बेटीयों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं देता। देश के साथ-साथ उन्होंने भी आक्रोशित होते हुए कहा कि जिस समय छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे समय में भी ऐसे अपराधी अन्यत्र शिकार की तलाश में घात लगाये हुए थे। उन्होंने दिसम्बर 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की चर्चा करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने मुझसे बड़ी मासूमियत से इस घटना के बारे में पूछा, मगर क्या उन्हें ऐसी घटना आगे घटित न होने का भरोसा दिया जा सकता है। निश्चित ही इस समय समाज को ईमानदार और निष्पक्ष रहकर आत्ममूल्यांकन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

राष्ट्रपति के बयान के आलोक में यदि महिला उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं का मूल्यांकन करें तो ज्ञात होता है कि अभी हाल ही में कोलकाता में डॉक्टर से किये गये यौन व्यवहार से देश भर में फैले आक्रोश और प्रदर्शनों के बीच विधायिका की एक बदरंग तस्वीर भी सामने आयी है। एसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, की ओर से जारी छलिया रिपोर्ट में 16 वर्तमान सांसदों और 135 विधायकों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध में मुकदमें दर्ज हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि दो सांसदों और 14 विधायकों पर दुष्कर्म के मामले चल रहे हैं। खास बात यह है कि बंगाल के सबसे अधिक जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। उधर हेमा रिपोर्ट के बाद केरल के फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के शोषण का मामला

आजकल चरम पर है। बदलापुर, महाराष्ट्र में अबोध बच्चियों का त्रासद प्रकरण, असम में 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएँ तो हमारी आँखों के सामने ही हैं। इनके अलावा प्रतिदिन समाचार पत्रों में यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसी घटनाओं को प्रचुर मात्रा में पढ़ा और समझा जा सकता है।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति महोदय की महिला उत्पीड़न को लेकर यह पीड़ा अनायास ही नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट भी बताती है कि यहां 16 मिनट में एक यौन दुष्कर्म घटना होती है। साथ ही प्रत्येक घण्टे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध घटित होते हैं। इनमें 10 फीसदी से भी अधिक यौन दुष्कर्म की घटनाएँ 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के साथ घटित होती हैं। कहना न होगा कि देश व प्रदेशों के मुकतलिफ हिस्सों में मासूम लड़कियों व महिलाओं के साथ घटने वाली यौन उत्पीड़न की वारदातों ने देश व समाज को झंकार और खर ख दिया है। लगता है निर्भया यौन उत्पीड़न की घटना के बाद समाज की सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। इसी कारण देश में यौन हिंसा की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं। केवल इतना ही नहीं ऐसी घटनाओं को रोकने के सभी उपाय भी निष्फल हो रहे हैं। देश-विदेश के स्तर पर जो भी रिपोर्ट आ रही हैं वे भी सब की सब यौन हिंसा के बढ़ते ग्राफ की ओर ही इशारा कर रही हैं। कहना न होगा कि बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातों से न केवल देश में, बल्कि विदेशों तक में अपनी किरकिरी हो रही है। उल्लेखनीय है कि देश में ऐसी घटनाओं का लगातार बढ़ना निश्चित ही गंभीर चिंता का विषय है। यौन उत्पीड़न की अधिकांश घटनाएँ आज कानूनविदों व समाजशास्त्रियों को नये सिरे से सोचने को मजबूर कर रही हैं। इस संदर्भ से जुड़े कुछ और आँकड़े खुलासा करते हैं कि भारत में यौन उत्पीड़न के मामले में लगभग 93 फीसदी दांपी पीड़िता के ही परिचित होते हैं।

सियासी गहमागहमी

कहीं भागव को हरवा तो नहीं देंगे शिवराज



प्रदेश की सबसे अधिक चर्चित विधानसभा सीट में आगामी दिनों में उप चुनाव होना है। दोनों ही प्रमुख राजनैतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। कांग्रेस ने जहां राजकुमार पटेल को टिकट दिया है वहीं, भाजपा की ओर से पूर्व सांसद रमाकांत भागव को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि उम्मीद इस बात की थी कि बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान को टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी आलाकमान ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और भागव को मैदान में उतारा। ऐसे में क्यास दम लगाये जा रहे हैं कि भले ही शिवराज व उनके परिवार के सदस्य पूरा दमखम लगाकर भागव के लिये प्रचार में जुटे हैं लेकिन भागव को खुद इस बात का डर है कि कहीं शिवराज सिंह चौहान ही उन्हें चुनाव में हरवा न दें। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में आने वाले चुनाव परिणाम में मालूम होगा।

दिग्विजय और पटवारी आखिर क्यों नहीं सध रही?



जितू

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह के लिये एक सीढ़ी तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस सीढ़ी में पटवारी रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के अनुसार पिछले दिनों रोशनपुरा चौराहे पर हुई बैठक में भी पटवारी ने दिग्विजय सिंह को काफी नजर अंदाज करने का प्रयास किया, यही नहीं बैठने के लिये भी पार्टी ने दिग्विजय सिंह के लिये आगे की जगह का स्थान तय किया लेकिन पटवारी ने आते ही उस स्थान पर अन्य नेताओं को बैठने के लिये कहा और दिग्विजय सिंह को दूसरी लाइन में जाकर स्थान लेना पड़ा। अब पार्टी आलाकमान एक नई चुनौती से कैसे पार पायेगी अब यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

PAC को जबब देने से बचाओ
SEBI से इन्स्टीट से बचाओ
उडानी पर जाप से बचाओ
कौन है ये सिडिकेट जो 'बुप को बच' रहा
है? और सबसे जरूरी, वो क्यों बचा रहा
है? सबका जल्द ही पर्दाफास होगा - देखते
जाइए!

-राहुल गांधी

काब्रेस नेता @RahulGandhi



कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी को बतौर कांग्रेस अध्यक्ष दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।



श्री खरगे जी ने गरीबों और लोषितों की
आवाज को सड़क से संसद तक उठाकर
देरा के हर व्यक्ति के हक और न्याय का
सकलप बखूबी निगाचा है।

-कमलनाथ

पटेल कांग्रेस अख्य

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

शिवसेना पार्टी को नई दशा और दिशा देने में उद्भव ठाकरे की रही है प्रमुख भूमिका

समता पाठक/जगत प्रवाह



शिवसेना महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी है। उद्भव पूर्व नेता और शिवसेना के संस्थापक श्री बालासाहेब ठाकरे के पुत्र हैं। उद्भव ठाकरे का जन्म, 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। उद्भव ठाकरे के पिता स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे थे। उनके पिता भारत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उद्भव ठाकरे का विवाह रश्मि ठाकरे से हुआ है। उनके दो पुत्र आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे हैं। राजनीति में आने से पूर्व शिवसेना के स्पष्ट उत्तराधिकारी के रूप में शायद ही कोई उद्भव ठाकरे को जनाता था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पार्टी के भीतर उद्भव ठाकरे ने कभी भी सक्रिय राजनीति में अपना ध्यान नहीं लगाया एवं अपने आप को वन्यजीव फोटोग्राफी में ही व्यस्त किये रखा। उद्भव ठाकरे एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे और वार्षिक प्रदर्शनियों में उनकी फोटोग्राफी काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने वर्ष 2002 के बीएमसी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उनके बेहतर प्रबंधन की वजह से शिवसेना पार्टी वास्तव में एक अच्छी स्थिति में पहुँच गयी। यह पहली बार था कि किसी ने उद्भव ठाकरे के नेतृत्व भरे गुणों और राजनीति के लिए एक बेहतर बानगी को देखा। उद्भव ठाकरे ने अप्रत्याशित रूप से सुविधियों प्राप्त की जब उन्हें शिवसेना के अगले प्रमुख बनाने जाने की घोषणा की गयी थी। जब उन्होंने 2002 के बीएमसी चुनाव में पार्टी की जीत के साथ शिवसेना को एक प्रमुख स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तब उनके पिता ने उहे पार्टी में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए जोर डाला।

वर्ष 2003 में उद्भव ठाकरे को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया और वह शिव सेना के नियंत्रण में रहे। मराठी अखबार सामना जो की पार्टी का प्रमुख मुखपत्र है और जिसकी स्थापना बालासाहेब ठाकरे ने की थी को उद्भव ठाकरे के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जून 2006 के बाद से उद्भव ठाकरे इस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे हैं। बालासाहेब ठाकरे के निधन के बाद से, उद्भव ठाकरे शिवसेना पार्टी की सत्ता में एकमात्र महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वर्ष 2006 में राज ठाकरे ने इस पार्टी को छोड़ दिया है। शिवसेना प्रमुख प्रचारक के रूप में काम करते हुए वर्ष 2002 में इन्होंने बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। विदर्भ, महाराष्ट्र के किसानों के लिए इन्होंने एक ऋण राहत अभियान का आयोजन किया था। उद्भव ठाकरे ने वर्ष 2012 में फिर से बीएमसी चुनाव में जीत के लिए शिवसेना का नेतृत्व किया था। उद्भव ठाकरे ने पार्टी की आक्रामक छवि में व्यापक परिवर्तन किया है। इसके अलावा एक उजवादी दल के रूप में लोगों के मध्य व्यापक छवि को परिवर्तित करते हुए दल को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है जोकि कुछ लोगों के द्वारा कल्याणकारी दल और सहयोगी दल के रूप में चर्चित किया गया था।

इस दीपावली अंदर से भी जगमगाओ

जगत प्रवाह, गोपाल।

आओ इस दीपावली अंदर से भी जगमगाएँ, दीप जलाकर मन को भी जगाएँ। दीपावली का त्योहार सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने और आत्मज्ञान जगाने का भी पर्व है। हम सभी को अपने अंदर के दीपक को जलाना चाहिए। हम सभी के जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस दिवाली अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ें। सारे त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व है। यह सारे त्योहार हमारी सभ्यता और



आज की बात
प्रवीण कवचकड़
स्वतंत्र लेखक

दीपावली पर कैसे रहें प्रेरित

आपने लक्ष्यों को निर्धारित करें - दीपावली के अवसर पर अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें।
नाए शुरूआत का मौका - दीपावली एक नई शुरूआत का प्रतीक है। यह हमें अपने पुराने विचारों और आदतों को छोड़कर नए सिरे से जीवन जीने का मौका देता है।
आशा और उत्साह - दीपावली हमें आशा और उत्साह से भर देती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।
सकारात्मक सोच रखें - नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालकर सकारात्मक सोच रखें।
आपने आप पर विश्वास करें - आपने आप पर विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें।
नाए कौशल सीखें - कुछ नया सीखने का कोशिश करें यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

संस्कृति में इस तरह से रचे बसे हैं कि असल में इन्हीं के माध्यम से समस्त समाज का निर्माण होता है। हमारे त्योहार सांस्कृतिक एकता की सबसे बड़ी धरोहर होने के साथ ही अर्थव्यवस्था का पहिया भी हैं। दीपावली के पर्व पर भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आते हैं जहाँ सारे नर नारी दीप जला कर उनका स्वागत करते हैं। इसीलिए यह दीपोत्सव है। दीपावली हमें सिखाती है कि अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। थोड़ी सी मेहनत और लगन से हम अपने जीवन के किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें हम सभी के अंदर बहुत सारी शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने का जरूरत है। दिवाली हमें अपनी इस शक्ति को पहचानने और उसे उपयोग करने का मौका देती है। यह हमें नए संकल्प लेने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें दो तरह के संदेश देता है। पहला खुद को अंदर से रोशन करने का और दूसरा अन्य लोगों के जीवन में सुविधियों का उजास जगाने का। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह आप इस त्योहार को विशेष रूप से मनाने हैं।

प्रकृति उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रकृति सेवक बनें

जगत प्रवाह, गोपाल।

आज के इस आधुनिक युग में मानव जीवन की गति इतनी तेज हो चुकी है कि वह प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने में चूक रहा है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान की तरक्की ने जहाँ हमें एक बेहतर जीवन जीने के साधन दिए हैं, वहीं हमने पर्यावरण को संतुलित रखने की अपनी जिम्मेदारी को कहीं पीछे छोड़ दिया है। इस कारण, हमारे चारों ओर प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इस लेख में, मैं एक महत्वपूर्ण विचार साझा करना चाहूँगा कि हमें केवल "प्रकृति के उपभोक्ता" बनने के बजाय, "प्रकृति के सेवक" बनना चाहिए। मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता हजारों साल पुराना है। हमारी पौराणिक कथाओं, संस्कृति और सभ्यता में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऋषि-मुनियों ने हमेशा प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का संदेश दिया है। प्रकृति को देवी-देवताओं के रूप में पूजना हमारे समाज में प्राचीनकाल से प्रचलित रहा है। लेकिन औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बाद यह सहअस्तित्व का भाव कहीं खो सा गया है। हमने प्राकृतिक संसाधनों को केवल उपभोग की वस्तु मान लिया है। पेड़ों को काटना, नदियों को प्रदूषित करना, भूमि का अत्यधिक दोहन करना - ये सब हमें प्रायति की ओर बढ़ने का रास्ता लगता है, लेकिन इसने हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया है। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, भूमि कटाव, जैव विविधता का विनाश - यह सब मानवता की चेतावनी है कि हमें अपने रास्ते को बदलना होगा। औद्योगिक क्रांति और आधुनिक तकनीक ने हमें संसाधनों के अंधाधुंध उपभोग की ओर धकेल दिया। हमने केवल अपने आराम और सुविधाओं के लिए संसाधनों का दोहन किया है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वन्यजीवन को नुकसान हुआ, प्रदूषण ने नदियों और हवा को विषाक्त बना दिया। हमने धरती के अद्वितीय



पर्यावरण की फिक
डॉ. प्रशांत शिल्पा

संसाधनों का दोहन किया और उन्हें अपने फायदे के लिए अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया और धरती के संतुलन को बिगाड़ दिया। अगर हम यही सोचते रहे कि प्रकृति केवल उपभोग की वस्तु है, तो भविष्य में हमारे पास रहने के लिए एक स्वस्थ धरती नहीं बचेगी। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण केवल एक कानूनी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी धरती हमें जीवन, जल, हवा, और भोजन देती है। हम इस धरती के कर्जदार हैं। अगर हम इस कर्ज को नहीं चुकाएँगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नहीं रख सकते। हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि प्रकृति का उपयोग करने के लिए है। हमें यह समझना होगा कि हमारा अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है, न कि प्रकृति हमारा उपभोग करने के लिए। एक सेवक के रूप में, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, उसका सम्मान करें और उसे स्वस्थ बनाए रखें। प्रकृति के सेवक बनने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ये कदम व्यक्तिगत, सामूहिक और समाजिक स्तर पर उठाए जा सकते हैं।

यह न केवल आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, बल्कि ऊर्जा संरक्षण में भी मदद करेगा। कचरे का पुनर्चक्रण करना अति आवश्यक है। कचरे का उचित निपटान और पुनर्चक्रण पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। घर में ही कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बाँटें और पुनर्चक्रण के लिए स्थानीय संगठनों की मदद लें। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक और गंभीर चुनौती है। इसके प्रभाव अब हर जगह देखे जा सकते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर का बढ़ना, अनियमित वर्षा और तूफानों की संख्या में वृद्धि - ये सब संकेत हैं कि हमें अपनी उपभोक्ता मानसिकता को छोड़कर प्रकृति की सेवा में जुटना चाहिए। हमें अपने जीवनशैली में स्थिरता लानी होगी और ऊर्जा की खपत को कम करना होगा। प्रकृति की सेवा के लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य हैं। हमें अपने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु मानते रहेंगे, तो हमें इसका मूल्य चुकाना होगा। हमें एक संवेदनशील समाज की ओर बढ़ना होगा, जहाँ हर व्यक्ति प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी महसूस करे। यह परिवर्तन केवल नीति निर्माण या कानूनों से नहीं हो सकता; इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाने होंगे। अंततः, हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब हम प्रकृति के सेवक बनेंगे, तब ही हम वास्तव में मानवीय मूल्यों को समझ पाएँगे। प्रकृति हमारी माँ है, और उसकी सेवा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस मानसिकता को अपना सकें, तो हम एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आइए, एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम प्रकृति के सेवक बनेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुस्थित, स्वस्थ और संतुलित धरती छोड़ेंगे। ऐसा करके ही हम अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ पाएँगे और आने वाले भविष्य को एक सुंदर धरती का उपहार दे पाएँगे।

उठने लगी आबादी बढ़ाने की मांग

चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन ने उठाई 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की मांग



प्रमोद भार्गव
विरिष्ठ साहित्यकार व
पत्रकार

जो चीजें कल तक अच्छी नहीं लग रही थीं, अब उन्हें अपनाने की मांग उठ रही है। कहा भी गया है कि प्रकृति अपना संतुलन बनाने का काम संसार के बावजूद कर लेती है। यही कुछ किस्सा आबादी के परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर पहले मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक चैंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने आंध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती में कहा कि 'अब बहुत हुआ लोग दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करें। हम ऐसे दंपतियों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार जल्दी ही ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके अंतर्गत दो से अधिक बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे।' इस बयान को तार्किक बनाते हुए नायडू ने कहा कि 'राज्य के कई जिलों में ऐसे गांव देखने में आ रहे हैं, जहां केवल बुजुर्ग देखे जा रहे हैं। कई बुजुर्गों के युवा या तो नौकरी के लिए विदेश चले गए हैं या फिर दूसरे राज्यों का रुख कर गए हैं। अगर एच दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर ही जनसंख्या स्थिर होगी।' इधर दक्षिण भारत के ही तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संसदीय परिषील के चलते लोगों से परिवार बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने जवाब बच्चे पैदा करने की स्थिति को लोकसभा सीटों के परिषील से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि 'अब नवविवाहित जोड़े कम बच्चे पैदा करने का विचार छोड़ दें। आखिर हम कम बच्चे पैदा करते तक सीमित क्यों रहें?' दरअसल अब भारत बढ़ा हो रहा है। इसलिए जनसंख्या बढ़ाने की चिंता वाजिब है। केंद्र सरकार द्वारा युवा भारत 2022 रिपोर्ट कहती है कि 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी, जो अभी 47 प्रतिशत से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल आयु वर्ग के हैं। किंतु आगामी 15 साल में यह दर गिरेगी। इसके दो बड़े कारण हैं। एक महिलाओं में प्रजनन दर निरंतर घट रही है। औसतन बच्चों का जन्म देने की जो दर 2011 में 2.4 थी, वह 2019 में 2.1 रह गई है। दूसरे, उत्तम होती स्वास्थ्य उपचार के चलते 2011 में प्रति 1000 लोगों पर 7.1 मौतें हो रही थीं,

यह स्थिति 2019 में घटकर छह रह गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोश (यूएनपीएफ) की भारतीय उम्र रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2011 में भारत में युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी, जो अब बढ़कर 29 साल हो गई है। यानी युवाओं की संख्या घट रही है। बुजुर्गों की संख्या 2036 तक भारत की जनसंख्या का कुल 12.5 प्रतिशत होगी। 2050 में यह 19.4 फीसदी और इस सदी के अंत तक 36 प्रतिशत होगी। यह बूढ़ी आबादी और युवाओं की घटती आबादी की भी देश के लिए चिंता का कारण होना चाहिए? अतएव नायडू और स्टालिन आबादी बढ़ाने का जो संदेश दे रहे हैं, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

भारतीय आबादी के सिलसिले में नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) की सांख्यिकीय रिपोर्ट-2018 ने देश में आबादी घटने के भयावह संकेत दिए थे। इस सर्वेक्षण के आधार पर 2018 में एक मां की उसके जीवन काल में प्रजनन दर 2.2 आंकी गई, लेकिन इस दर में गिरावट के चलते वह दिन दूर नहीं, जब देश में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) दो रह जाए? इस विशय के जानकार लोगों का मानना है कि यदि भारत ने यह आंकड़ा छुड़ लिया तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और फिर कुछ वर्षों में घटने लगेगी। बालिकाओं के गिरते लिंगानुपात के कारण भी यह स्थिति बनेगी। यह स्थिति सामाजिक विकृतियों को बढ़ावा देने वाली साबित हो सकती है। ऐसे में विवाह की उम्र बढ़ाना निकट भविष्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकती है।

एसआरएस की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे जन्म के समय लिंगानुपात के हैं। जैविक तौर पर जन्म के समय सामान्य लिंगानुपात प्रति एक हजार बालिकाओं पर 1050 बालकों का रहता है या प्रति एक हजार बालकों पर 950 बालिकाओं का एसआरएस की रिपोर्ट की मानें तो भारत में लिंगानुपात प्रति एक हजार बालकों पर बालिकाओं के जन्म के आधार पर गिना जाता है। यह 2011 में 906 था, जो 2018 में गिरकर 899 रह गया। केरल और छत्तीसगढ़ छोड़ देश के ज्यादातर राज्यों में पुत्र की आकांक्षा अधिक देखी गई है। बिगड़ते लिंगानुपात विवाह व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर डालता है। बिगड़ते लिंगानुपात के चलते इस स्थिति में सुधार के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। भारत इस अनुपात को सुधार सकता है, क्योंकि उसके पास 15 से 49 वर्ष के प्रजनन योग्य आयु वर्ग के लोगों का बड़ा समूह है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विवाह की आयु घटाने के साथ अवैध संतान को वैधानिकता देना कानूनी रूप से अनिवार्य करना होगा। साथ ही लिंग

परीक्षण और कन्या भ्रूण को कोख में ही नष्ट करने के उपाय बंद करने होंगे। इस हेतु आर्थिक समानता के उपायों के साथ युवाओं को प्रजनन, स्वास्थ्य शिक्षा और लैंगिक समानता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना होगा। जैसा की अब नायडू और स्टालिन कर रहे हैं। अक्सर भारत या अन्य देशों में बढ़ती आबादी की चिंता की जाती है। लेकिन अब भारत में कुछ धार्मिक समुदायों और जातीय समूहों में जनसंख्या तेजी से घटने के

एक राष्ट्र के स्तर पर कोई देश विकसित हो या अ विकसित हो अथवा विकासशील, जनसंख्या के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष एक पटार की समाजिक व वैज्ञानिक सोच का प्रतीकरण करते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में जनसंख्या में बदलाव एक जैविक घटना होने के साथ-साथ समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आधारों को प्रभावित करने का कारण बनती है। इसलिए भारत में जब पांच अल्पसंख्यक समुदायों में से एक पारसियों की आबादी घटती है तो उनकी आबादी बढ़ाने के लिए भारत सरकार मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ मुस्लिमों को छोड़ अन्य धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के कठोर उपाय किए जाते हैं। यह विरोधाभासी पहलू मुस्लिम समुदाय की आबादी तो बढ़ा रहा है, लेकिन अन्य धार्मिक समुदायों की आबादी घट रही है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुरा लगाने के लिए एक समान नीति को कानूनी रूप दिए जाने की मांग कई समुदाय कर रहे हैं।

संकेत मिल रहे हैं। भारत में जहां आधुनिक विकास व विस्थापन के चलते पारसी जैसे धार्मिक समुदाय और आदिवासी प्रजातियों में आबादी घट रही है, वहीं उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचलन में आ जाने से एक बड़ा आर्थिक रूप से सक्षम समुदाय कम बच्चे पैदा कर रहा है। एक राष्ट्र के स्तर पर कोई देश विकसित हो या अ विकसित हो अथवा विकासशील, जनसंख्या के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष एक प्रकार की सामाजिक व वैज्ञानिक सोच का प्रतीकरण करते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में जनसंख्या में बदलाव एक जैविक घटना होने के साथ-साथ समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आधारों को प्रभावित करने का

कारण बनती है। इसलिए भारत में जब पांच अल्पसंख्यक समुदायों में से एक पारसियों की आबादी घटती है तो उनकी आबादी बढ़ाने के लिए भारत सरकार मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ मुस्लिमों को छोड़ अन्य धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के कठोर उपाय किए जाते हैं। यह विरोधाभासी पहलू मुस्लिम समुदाय की आबादी तो बढ़ा रहा है, लेकिन अन्य धार्मिक समुदायों की आबादी घट रही है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुरा लगाने के लिए एक समान नीति को कानूनी रूप दिए जाने की मांग कई समुदाय कर रहे हैं। हालांकि यह कानून बनाना जाना आसान नहीं है। क्योंकि जब भी इस कानून के प्रारूप को संसद के पटल पर रखा जाएगा तब इसे कथित बुद्धिजीवी और उदारवादी धार्मिक रंग देने की पुरजोर कोशिश में लग जाएंगे। बावजूद देशहित में इस कानून को लाया जाना जरूरी है, जिससे प्रत्येक भारतीय नागरिक को आजीविका के उपाय हासिल करने में कठिनाई न हो। अभी तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी हिंदुओं में आबादी बढ़ाने की पैवी करते रहे हैं, किंतु अब नायडू और स्टालिन ने आबादी बढ़ाने की जो वाकालात की है, उससे संघ और भारत सरकार को बल व प्रोत्साहन मिल सकता है?

भारत में समग्र आबादी की बढ़ती दर बेलगाम है। 15 वीं जनगणना के निष्कर्ष से साबित हुआ है कि आबादी का घनत्व दक्षिण भारत की बजाए, उत्तर भारत में ज्यादा है। लैंगिक अनुपात भी लगातार बिगड़ रहा है। देश में 62 करोड़ 37 लाख पुरुष और 58 करोड़ 65 लाख महिलाएं हैं। हालांकि इस जनगणना के सुखद परिणाम यह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर में 3.96 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.7 प्रतिशत रही, जबकि 2001 की जनगणना में यह 19.92 फीसदी थी। वहीं 2011 की जनगणना में मुसलमानों की आबादी में वृद्धि दर 19.5 प्रतिशत रही, वहीं 2001 की जनगणना में यह वृद्धि 24.6 प्रतिशत थी। सुफाद है, मुस्लिमों में आबादी की दर हिंदुओं से अधिक है। विसंगति यह भी है कि पारसियों व ईसाइयों में भी जन्म दर घटी है। जबकि उच्च शिक्षित व उच्च आय वर्ग के हिंदू एक संतान पैदा करने तक सिमट गए हैं, जबकि वे तीन बच्चों के भरण-पोषण व उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने में सक्षम हैं। भविष्य में वे ऐसा करें तो समुदाय आधारित आबादियों के बीच संतुलन की उमीद की जा सकती है?

आमतौर से जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिगत चीन को परिवार नियोजन संबंधी नीतियों को आदर्श रूप में देखा जाकर उनका विस्तार भारत में किए जाने की मांग उठती

रहती है। चीन में आबादी को काबू के लिए 1979 में 'एक परिवार एक बच्चा' नीति अपनाई थी। लेकिन यह गलतफहमी है कि चीन में आबादी इस नीति से काबू में आई। सच्चाई यह है कि 1949-50 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति के जरिए जो सामाजिक बदलाव का दौर चला उसके चलते वहां 1975 तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आम आदमी की पहुंच में आ गया था। साम्यवादी दलों के कार्यकर्ताओं ने भी वहां गांव-गांव पहुंचकर उत्पादक समन्वयक की हैसियत से काम किया और प्रशासन से जरूरतों की आपूर्ति कराई। नतीजतन वहां आबादी के 25-30 साल के भीतर ही राष्ट्रीय विकास के लिए एक आबादी जरूरी है, यह वातावरण निर्मित हो चुका था।

'एक परिवार, एक बच्चा' नीति चीन में कालांतर में विनाशकारी साबित हुई। इस नीति पर कड़ाई से अमल का हथ्र यह हुआ कि आज चीन में अनेक ऐसे वंश हैं, जिनके बूढ़े व असमर्थ हो चुके मां-बाप के अलावा न तो, कोई उत्तराधिकारी है और न ही कोई सगा-संबंधी है। लेकिन अब स्त्री-पुरुष का अनुपात इतना गड़बड़ा गया है कि चीन ने इस नीति को नकारते हुए एक से अधिक बच्चे पैदा करने की छूट दे दी है। आबादी नियंत्रित करने के लिए कठोरातन बरतने के ऐसे ही दुष्परिणाम जापान, स्वीडन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहे हैं। इन देशों में जन्म-दर घटता जनक स्थिति तक घट गई है। जापान में मुहम्मल स्वास्थ्य सेवाओं और पर्याप्त आबादी नियंत्रण उपायों के चलते बूढ़ों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। इन बूढ़ों में सेवानिवृत्त पेंशनधारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए वे जापान में आर्थिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बड़ा कारण बन रहे हैं।

प्रकृतिजय जैविक घटना के अनुसार एक संतुलित समाज में बच्चों, किशोरों, युवाओं, प्रौढ़ों और बुजुर्गों की संख्या का एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। अन्यथा यदि कोई एक आयु समूह की संख्या में गैर अनुपातिक ढंग से वृद्धि दर्ज हो जाती है तो यह वृद्धि उस संतुलन को बिगाड़ देगी, जो मानव समाज के विकास का प्राकृतिक आधार बनता है। भारत में जिस तेजी से पेंशनधारी बुजुर्गों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, वह आर्थिक व स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से तो संकट पैदा कर ही रही है, देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं के हित का एक बड़ा हिस्सा भी बुजुर्गों पर न्योछावर किया जा रहा है। संतुलित मानव विकास के लिए यह दुराभिसंधि घातक है। लिहाजा आबादी बढ़ाने की जो अपील नायडू और स्टालिन कर रहे हैं, उसका स्वागत करने की जरूरत है।

बाल अपराध और सोशल मीडिया



में
-रघु ठाकुर

5 सितम्बर के अखबार और मीडिया पर चार खबरें बलात्कार या बच्चियों के साथ अपराध की चर्चा हैं। इन सभी अपराधों की शिकार होने वाली बच्चियां कम उम्र और अधिकांश में अपराधी भी कम उम्र वाले ऐसी ही एक और खबर सोशल मीडिया

पर आई है कि मध्यप्रदेश के सागर जिले में किसी स्कूल के एक छात्र ने छात्रा के साथ बलात्कार किया। पहली तीन खबरों का जो जिक्र मैंने किया है, वे भी मध्यप्रदेश में मुरैना, नर्मदापुरम और हरदा की हैं। आमतौर पर अपराध की घटनाएं अखबार में राज्य के पत्रों पर छपती हैं। इसलिए प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में हुई घटनाओं के बारे में सूचना कम मिल पाती है। अगर सारे देश के अखबार देखे जायेंगे तो शायद ही कोई प्रदेश बचेगा जहां ऐसी घटनाएं न घट रही हों। ये घटनाएं सूचनाएं भी हैं, साथ ही समाज व देश की राजनीतिक व्यवस्था व न्यायपालिका के लिए भी गहरा संदेश है। मैं नहीं जानता कि समाज, न्यायपालिका व राजसत्ता ने इन घटनाओं को मात्र एक अपराध के रूप में देखा है या फिर इनके गहरे निहितार्थ को समझने का प्रयास भी किया है।

यह जानना भी कठिन है क्योंकि इन तीनों के साथ किसी का भी कोई सीधा संवाद सम्भव नहीं। इनकी प्रतिक्रिया जानना भी कठिन है। लगभग हर मीडिया, चैनल और अखबारों के एक दो पेज या बड़ा हिस्सा धर्म के नाम पर, कर्मकांड और उपदेश के लिए सुरक्षित रहता है जिनमें धर्मगुरुओं के भारी भारी शब्दों के उपदेश भी मोटे अक्षरों में छपते हैं। परंतु ये खबरें इन धर्मगुरुओं के ऊपर कोई प्रभाव डालती नहीं दिखती। कई बार ऐसा लगता है कि ये धर्मोपदेशक शायद अपना ही उपदेश पढ़ते हैं और अपनी ही फोटो देखते हैं। इन गंभीर अपराधों की खबरों को जो धर्म और समाज दोनों से जुड़ी हैं वे या तो पढ़ते नहीं हैं या फिर पढ़ कर उन्हें दृष्टि से ओझल कर देते हैं। उन पर प्रतिक्रिया करना तो दूर की बात है। शायद वे जानते हैं कि निर्गुण धार्मिक उपदेश देना सुरक्षित कार्य और सगुण बोलना सत्ता, व्यवस्था और समाज की नाराजगी को मोल लेना है। एक अलिखित समझौता सा धर्मगुरुओं, राजनेताओं और समाज के बीच है कि जो होता है वह होता रहे, तुम अपनी गति से आगे बढ़ो, हम अपने उपदेश देते रहेंगे।

शायद यह साहस गांधी में ही था कि वे अपनी प्रार्थना-सभाओं में उन घटनाओं पर सगुण टिप्पणी करते थे जो समाज, देश और दुनिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती थीं। मेरी राय में इस पर भी विचार होना चाहिए कि अखबार इन घटनाओं के पीछे क्या कारण हैं। वे क्यों हल नहीं की जा सकतीं। मेरी वर्षों से यह राय बनी है कि समाज में निरंतर बढ़ रहे अपराध के पीछे आबादी की वृद्धि-व्यवस्था की असफलता या पक्षधरता- और नई मशीनी सभ्यता और तकनीक भी बड़े कारण हैं। आबादी की चर्चा इसलिए कि आबादी की वृद्धि का बोझ देश और प्रकृति पर इतना बढ़ चुका है कि वह इंसान की मानवीय जरूरतों की पूर्ति करने में भी असफल हो रही है। आज अगर देश में कुछ वर्षों में

ही सामाजिक मान्यता के बगैर लड़कें और लड़कियां का सहजीवन, जिसे शिलव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, लाखों की संख्या में पहुंच चुका है तो क्या इसका एक कारण आबादी की वृद्धि नहीं है? जवान बच्चों के पास अगर अपनी मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लायक स्थान नहीं होंगे, वे विधिवत शादी और विवाह के बाद रहने के लिए जरूरी स्थान भी नहीं पा सकेंगे तो यह सहजीवन का चलन बढ़ेगा। भले ही समाज की बहुसंख्या अभी इसे अस्वीकार करे।

आजकल जो बाल अपराध हो रहे हैं उनमें एक बड़ा कारण पोर्न-साइट्स का भी है। सोशल मीडिया पर जितने समूह हैं, विशेषतः जो विज्ञापनों से चलते हैं, उनमें अधिकांश विज्ञापन अश्लील और नग्नता के होते हैं। यहां तक कि कुछ समूह जो वैचारिक संदर्भों या नाम से हैं, उनके भी समाचारों के अंदर के समाचारों में ऐसे ही चित्र नजर आते हैं। यह बाजार का व्यापारिक कौशल है या विज्ञापनदाताओं की आवश्यकता, या समूह चलाने वालों की आर्थिक लाचारी है, इसका ठीक उत्तर तो उन्हीं से मिल सकता है। पर यह निर्विवाद है कि बढ़ते बाल अपराधों में पोर्न-साइट्स और चाइल्ड पोर्नोग्राफी बड़ी हद तक जवाबदेह है।



शारीरिक संबंध बनाने की इंसानी भूख और स्थानाभाव ने एक विकृत रूप लेना शुरू कर दिया है। बड़े शहरों के सार्वजनिक पार्क, होटल और यहां तक कि सार्वजनिक यातायात के वाहन, मेट्रो आदि भी अब भयावह रूप ले रहे हैं। मेरे कई सुशिक्षित मित्रों ने बताया कि दिल्ली के मेट्रो में चलना अब इसलिए कठिन हो रहा है कि भीड़ के अलावा लड़के लड़कियों के संबंध की अवस्था विकृत हो रही है। पूना के एक सार्वजनिक पार्क में मैंने स्वयं ऐसे दृश्य देखे हैं और पार्क के मुख्य दरवाजे पर जो रजिस्टर प्रतिक्रियाओं के लिए रखा था उसमें लिखा था कि इसका नाम बदल कर उक्त पार्क पाक्य रखा जाये ताकि कम से कम उन महापुरुषों का सम्मान बना रहे। जिनके नाम पर पार्क बनाया गया है।

आजकल जो बाल अपराध हो रहे हैं उनमें एक बड़ा कारण पोर्न-साइट्स का भी है। सोशल मीडिया पर जितने समूह हैं, विशेषतः जो विज्ञापनों से चलते हैं, उनमें अधिकांश विज्ञापन अश्लील और नग्नता के होते हैं। यहां तक कि कुछ समूह जो वैचारिक संदर्भों या नाम से हैं, उनके भी समाचारों के अंदर के समाचारों में ऐसे ही चित्र नजर आते हैं। यह बाजार का व्यापारिक कौशल है या विज्ञापनदाताओं की आवश्यकता, या समूह चलाने वालों की

आर्थिक लाचारी है, इसका ठीक उत्तर तो उन्हीं से मिल सकता है। पर यह निर्विवाद है कि बढ़ते बाल अपराधों में पोर्न-साइट्स और चाइल्ड पोर्नोग्राफी बड़ी हद तक जवाबदेह हैं। डिजिटल कम्पनियां भी अपने व्यापार के लिए पोर्नोग्राफी को न केवल बढ़ावा दे रही हैं बल्कि बड़े पैमाने पर बेच रही हैं। यूनिसेफ के अनुसार भारत के 43 करोड़ बच्चे नाबालिग हैं। छोटे घरों में जब वे अपने माता-पिता को यौन संपर्कों में देखते हैं तो उनके बाल-मन

पूर्णतः मोबाइल की पाबंदी लगाई जाये तो यह भी सम्भव और व्यावहारिक नहीं लगता क्योंकि अब तो अनेक शैक्षणिक-सुरक्षात्मक कार्यों के लिए मोबाइल जरूरी हो गया है। दूसरे, अपनी नासमझी के तहत या कुछ लाचारी और अभ्यास के चलते मातायें खुद बच्चों को साल दो साल की उम्र से मोबाइल पकड़ा देती हैं। मैं अमूमन यात्राओं में देखता कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए माताएं उन्हें मोबाइल देती हैं। मोबाइल देखते हुए बच्चे को खाना खिलाते हुए वह

बहुत प्रसन्नता के साथ बताती हैं कि वह बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता। वे अपने बच्चों में मोबाइल की लत पैदा कर रही हैं। अपने ही बच्चों के भविष्य को बर्बादी की ओर ले जा रही हैं।

मेरी राय में बाल अपराधों व यौन अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-

1- सरकार और समाज, आबादी नियंत्रण पर प्रमुखता से ध्यान दें, वरना स्थितियां दिनों-दिन भयावह होंगी।

2- भारत सरकार को भारत में ऐसी इंटरनेट व्यवस्था शुरू करनी चाहिए जिनमें यशरीली तौर पर ही पोर्नोग्राफी, स्पैम या फिशिंग मैसेज के माध्यम से अश्लील दृश्य न आ सकें।

3- समाज व धार्मिक संस्थाओं को यह समझना होगा कि अब यह मामले केवल अपराधिक नहीं बल्कि समाज के विकृत होने के प्रमाण हैं।

4- क्या राजनेता, सामाजिक नेता व धर्मगुरु यह खुले तौर पर कहने का व स्वीकारने का साहस करेंगे कि यह उनके लिए भी कसौटी है?

5- न्यायपालिका के निर्देश व आदेश कुछ आए हैं। परंतु यह बहुत स्पष्ट या कारगर हैं ऐसा नहीं लगता। तमिलनाडु न्यायपालिका ने इस पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में जो निर्णय दिया था वह कानून की परिभाषा की दृष्टि से तो मैं नहीं कहता पर समाज जीवन की परिभाषा के अनुसार नितान्त गलत था। इसके खिलाफ अरील में सर्वोच्च न्यायालय ने

पर जो अस्सर होता है वह भी उन्हीं यौन क्रिया और संबंधों के बारे में प्रेरित करता है। एक अध्ययन के मुताबिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में से 97 फीसदी बच्चे औसतन 43 मिनट स्कूल में भी मोबाइल देखते हैं। सम्भव है कि इस समय में भी वे अधिकांश तौर पर ऐसे ही चित्र देखते हों। आजकल बच्चों में भी ड्रग्स का व्यापार बढ़ा है। ड्रग्स भी पोर्नोग्राफी के साथ बाल-अपराध का बड़ा कारण बन गई हैं। कहने को निजी कचब के विज्ञापन में गुगल ने औसतन पंद्रह अरब स्पैम और फिशिंग मैसेज को ब्लॉक किया है। गुगल एंड्रायड एप्स के दो सौ अरब स्कैनिंग के दावे किए हैं। परंतु इन्हीं को कोई प्रामाणिकता नहीं है। भारत सरकार ने जो आईटी रूल्स 2011 व 2021 के तहत जो नये नियम बनाये हैं उनके अनुसार इंटरनेट कंपनियों को अपनी साइट्स पर से पोर्नोग्राफिक मैसेज हटाना चाहिए। यह नियम बनाना तो आसान था परंतु इन साइट्स पर से ये मैसेज हटाये गए या नहीं, इनका नियंत्रण व अध्ययन कैसे सम्भव हो सकता है। इसका कोई इलाज या तो इंटरनेट के मालिक खोज सकते हैं, उनकी कम्पनियों के शोधकर्ता तथा तकनीकी विशेषज्ञ खोज सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत समाज, राजसत्ता या धार्मिक जमातें कर सकती हैं। अगर नाबालिग बच्चों पर

फैसला देकर उच्च न्यायालय तमिलनाडु के निर्णय को रोकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधी कंटेंट न कोई साइज करेगा, न डाउनलोड करेगा, यह भी बहुत प्रभाव या न्यायपालिका कार्रवाई कैसे करेगी? अगर कुछ चंद लोगों पर कोई कार्रवाई भी हुई तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? यह तो कैसर की बीमारी में जुकाम की दवा देने जैसा होगा।

अब तो साफतौर पर यह निर्णय करना होगा कि अगर इंटरनेट और डिजिटल कंपनियां ही इसके निर्माण, प्रसारण व विज्ञापन पर रोक नहीं लगाती तो इनको ही पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाये। भले ही उस समय देश को कुछ परेशानी या तकलीफ उठानी पड़े। उसके लिए भी समाज को तैयार रहना होगा। तथा भारत सरकार व तकनीकी विशेषज्ञों को कुछ ऐसे उपाय के साथ इंटरनेट का विकास करना होगा कि ऐसी सामग्री भेजी न जा सके। क्या इंटरनेट का कोई तकनीकी सुरक्षा कचब बन सकता है। यह अभी से चिंता व शोध का विषय होना चाहिये।

कलम के सिपाही

भारत के शीर्ष
50 पत्रकारों में
से एक हैं अंशुमन

अंशुमान तिवारी वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे समूह की इंडिया टुडे पत्रिका के संपादक हैं। वह दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख और उप संपादक थे। उन्होंने डेंटन न्यूज और फाइनशिपल टाइम्स, लंदन के साथ दुनिया भर में यूनिंग के एक तत्व के रूप में काम किया है। उनके ब्लॉग अर्थात् को आईटीबी द्वारा सर्वश्रेष्ठ हिंदी ब्लॉग की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। अंशुमान तिवारी का जन्म 25 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन, कानपुर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनके काम हिंदी/अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, एम.ए., भूगोल और हिंदी साहित्य में बी.ए. की डिग्री है, और मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में मास्टर डिप्लोमा में एक पेशेवर डिग्री है। 1990 के दशक की शुरुआत में कानपुर में, उन्होंने स्टिक एक्सचेंज के स्ट्रिंगर के रूप में अपना करियर स्थापित किया। संवाददाताओं से लेकर एक लेखक तक, उन्होंने विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों को अपनाया है और अपने पूरे करियर में व्यापक आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय बाजार रिपोर्ट को कई मॉडलों में पेश किया है। वह राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख-दैनिक जागरण के पद पर दिल्ली सीईओ/ब्यूरो चीफ/कॉमनवेल्थ गेम्स 2012 की तीन साल की प्रदर्शनी सहित अपनी संपत्ति के लिए बहुत अधिक हार्ड-प्रोफाइल समाचारों के साथ एक प्रमुख खोजी स्तंभकार हैं। अंशुमान को नई दिल्ली में इंडिया टुडे पत्रिका के संपादक के रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इससे पहले, वह 2008 से 2013 तक दैनिक जागरण (भारत का सबसे अधिक आबादी वाला हिंदी दैनिक समाचार पत्र) के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख, ब्यूरो प्रमुख और समूह योगदान प्रमुख और उप संपादक थे। तिवारी डिजिटल हिंदी आर्थिक सामग्री साइट, मनी भास्कर के प्रधान संपादक थे। बीबी कॉर्प के स्वामित्व में वह नियमित रूप से दैनिक समाचार पोर्टल डालियो (इंडिया टुडे) के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं। हिंदी में एक विरलेपक के रूप में, वे 15 वर्षों से दैनिक जागरण में साप्ताहिक क्रॉनिकल अपर्ट/अधोत में लिख रहे हैं। अंशुमान एक आर्थिक व्याख्याकार और स्तंभकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन्होंने दैनिक भास्कर समूह के लिए अभिनव और मालिकाना बहुभाषी सामग्री, पहला डिजिटल चर्टिकल डिजाइन और निर्मित किया है। उन्हें खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है। एक मीडिया रिसर्च के अध्ययन में पाया गया कि अंशुमान भारत के शीर्ष 50 पत्रकारों में से एक हैं। हिंदी पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार 2013 मिला।

कमलनाथ की सक्रियता से
मध्यप्रदेश कांग्रेस में आई स्फूर्ति

(पेज 1 का शेष)
बल्कि उन्होंने अपनी दूसरी पीढ़ी यानी कि अपने बेटे नकुलनाथ को भी छिंदवाड़ा की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया है। लोकसभा चुनाव के चार महीने बाद ही अब सच सम्मने आने लगा है, जो बड़ी-बड़ी झूठी बातें करके, जयवंतों को प्रलोभन देकर जो सीटें जीती जन्ता के सम्मने वह सब झूठी बातें सम्मने आ रही हैं।

कमलनाथ को सक्रिय राजनीति से दूर रखने से आठ महीने में ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पहुंची बड़ी क्षति, नेता और कार्यकर्ताओं में मनभेद और मतभेद दोनों बढ़ा

अब कमलनाथ दूर करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उपजे मनभेद को

मध्यप्रदेश कांग्रेस के नेताओं के मन में लगातार फैल रहा असंतोष और आपसी मतभेद को सुगुणाहट पार्टी आलाकमान तक पहुंच गई है। पार्टी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली विधानसभा चुनाव की हार से अभी तक संभली भी नहीं थी कि पार्टी नेताओं के बीच के आपसी मतभेद, इंगो प्रॉब्लम, आये दिन हो रहे इगहों की शिक्षायात लगातार उच्च स्तरीय नेताओं तक पहुंच रही थी। क्या यही कारण है कि पार्टी आलाकमान राहुल गांधी ने स्वयं इन सभी मतभेदों पर विराम लगाने का निर्णय लिया और एक के बाद एक तीनों ही राज्यों के वरिष्ठ नेताओं से बैठक कर पार्टी को नई दिशा देने के लिये कार्य आरंभ करने का विचार किया। इसी क्रम में पिछले दिनों राहुल गांधी पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के दिल्ली स्थित निवास पर मिलने पहुंचे और दोनों के बीच में लगातार दो घंटे तक कई प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। बंद कमरे में राहुल गांधी और कमलनाथ की बैठक से एक तरफ जहां सिवासी गतिधारा फिर से सक्रिय हो गया है वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी तथा उनके समर्थकों में कुछ नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। कमलनाथ और राहुल गांधी की यह 42 दिन के भीतर दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 03 सितंबर को कमलनाथ ने राहुल गांधी के आवास पर मुलाकात की थी। राजनैतिक विरलेपकों ने राहुल गांधी से कमलनाथ को इस मुलाकात को सामान्य बताया तो वहीं कुछ विरलेपकों ने इसे "टाइगर इव कॉमिंग बैक" बताया है। हालांकि अगर कमलनाथ के कार्यों और उनकी कार्यशैली पर नजर डाली जाये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कमलनाथ एक सशक्त लीडरशिप और विचनरी नेता हैं। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में न सिर्फ पार्टी को गति देने का कार्य किया बल्कि पार्टी नेताओं को आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिये प्रेरित किया। लेकिन धोखेबाज ज्योतिरदिल सिंधिया के स्वध्वंसा लिये गये एक गलत फैसले ने कमलनाथ को उनके विचन अनुसर कार्य करने से रोक दिया।

विज्ज के साथ कार्य करते हैं कमलनाथ

पार्टी आलाकमान इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि कमलनाथ एक विचन के साथ पार्टी का संचालन करने में सक्षम हैं। बीच में कुछ अपने ही नेताओं के बगलवाये जाने पर पार्टी ने कमलनाथ को

सक्रिय रूप से थोड़ा दूर कर दिया था लेकिन इस बीच में पार्टी और नेताओं को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो क्षति हुई है उससे पार्टी ने अपनी गलती को सुधारने पर विचार किया और क्या अब फिर कमलनाथ को प्रमुख जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर पार्टी मध्यप्रदेश में कमलनाथ को कोई प्रमुख जिम्मेदारी देती है तो फिर बाकी अभी प्रमुख पदों पर आसीन नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी।

2018 में प्रदेश की राजनीति में हुए थे शिफ्ट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजनीति से मध्य प्रदेश की ओर रुख किया था। उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना गया था और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस सत्ता में महज 15 माह रही, आपसी खिंचतान के चलते सत्ता हाथ से खिसक गई और भाजपा को फिर सत्ता में वापसी हो गई। उसके बाद से कमलनाथ का दायरा लगातार सिमटता गया और वर्तमान में उनकी ज्यादा सक्रियता छिंदवाड़ा तक सीमित है। सिवासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। साध ही यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि कमलनाथ की राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर सक्रियता ब्यौंगी और आगामी चुनाव में वह बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

जीतू पटवारी छेमे में निराशा

राहुल गांधी और कमलनाथ की लंच मीटिंग से मध्यप्रदेश कांग्रेस का जीतू पटवारी छेमा नाराज बताया जा रहा है। जीतू पटवारी के पीसीसी चीफ बनने से पहले ही दोनों नेताओं की अनबन थी। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि मध्यप्रदेश कांग्रेस के संगठन में निरुक्तियों होनी थीं। जो कि अब होल्ड पर रखी जा सकती हैं। इसमें कमलनाथ का दखल देखने को मिल सकता है। उधर विरलेपक कह रहे हैं कि कमलनाथ किसी दूसरे राज्य को बांगडोर अपने हथों में नहीं धारंगे बल्कि मध्यप्रदेश में एंक्रिय हो सकते हैं। राजनैतिक विरलेपकों के अनुसार अभी की हालिया मुलाकात ने पूरे समीकरण को ही बदलकर रख दिया है।

उपवास कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को दिया प्रोत्साहन

राहुल गांधी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही कमलनाथ राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहा पर आयोजित उपवास कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। कमलनाथ का यह कदम निश्चित तौर पर प्रदेश में उनके बढ़ते कद और कदम को और इशारा करता है। इस धरना प्रदर्शन में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे और दोनों नेताओं ने धरना प्रदर्शन को मजबूती दी। इस दौरान कमलनाथ ने अपने परिचित अंदाज में महिलाओं और बेटियों पर ही इस अत्याचार पर मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश लड़कियों और महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बलात्कार के मामलों में मध्यप्रदेश तीसरे

स्थान पर है। कमलनाथ ने कहा, "भाजपा सरकार की असवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य महिला आयोग को अध्यक्ष का पद पिछले चार साल से खाली पड़ा है। लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कमलनाथ को राजनैतिक सुइबूज और समझ की वारिष्ठ विषयों दल भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी करते हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेक पहल से राज्य की लाखों छात्राओं के सपनों को मिले पंख

(पेज 1 का शेष)
सीएम ने अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना का प्रचार जोर-शोर से किया जाए जिससे लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी मिले और अधिक से अधिक छात्र इस योजना के साथ जुड़कर अपने भविष्य को उजल कर सकें। इस योजना में पीजी और स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है।

छात्र-छात्राओं में है उत्साह का माहौल

इस योजना को लेकर छात्र-छात्राओं का कहना है कि सरकार को इस योजना का लाभ उन छात्रों का सबसे ज्यादा मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। बजटमुक्त लोन मिलने से परिजन भी ज्यादा प्रेरित नहीं दे पाएंगे। इस योजना का लाभ लेकर छात्र अपने भविष्य को बना सकते हैं।

नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों के बच्चों को भी मिलेगा लाभ

प्रदेश के नक्सल हिंसा से प्रभावित जिले के विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए बिना ब्याज के एजुकेशन लोन मिलेगा। शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत की दर से लोन दिया जाएगा। यह लोन मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टरों को इसके लिए विरोध अभियान चलाने को कहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया, इस योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है।

04 लाख तक लोन

ऐसे छात्रों जिनके परिवारों की वार्षिक आय 02 लाख से कम है। उनको मोटेतरिम अवधि के बाद ऋण फिलॉ के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जाएगा। योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण को अधिकतम सीमा 04 लाख रुपए निर्धारित है।